

मैं भी हिंदू लेकिन नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं : सिद्धारमैया

एजेंसी  मैसूर
www.dailypioneer.com

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव को



खतरा पहुंचाने वाले किसी सिखाफ कानून कार्रवाई की वह किसी भी धर्म या राजन-भाजपा नेता सीटी रविवर भाजपा विधायक बसनगौड़ कथित भड़काऊ बयानों के गई एफआईआर पर प्रतिक्रिया हुए सिद्धारमैया ने कहा, मैं और मेरे नाम में ईश्वर और है लेकिन शांति बनाए रख है भाजपा नेता भड़काऊ तो पुलिस क्या करे? यह रा यह सार्वजनिक व्यवस्था क में है। उन्होंने यह टिप्पणी ग दौरान हसन रोट हद्दसी ने माने जाने के बाद मैसेर ह



मीडिया को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही राहत स्पष्ट किया कि पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि केवल सांवला देने के लिए है जीवन के मूल्यों का मुआवजा नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार शोक संतप्त लोगों को सांवला देने के लिए राहत प्रदान करती है लेकिन मृतक की जगह को नहीं ले सकता। दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी, इसके लिए सीधे तौर पर राज्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री कुष्णा बायेंगौड़ा को परिवारों से मिलने और सहायता की घोषणा करने का निर्देश दिया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह सहायता पीड़ितों की पृष्ठभूमि से जुड़ी है सिद्धार्थैया ने कहा कि ज्यादातर मुक्तक दिहड़ि मजदूर और छात्र थे। शोधमंस्थल मामले में सिद्धार्थैया ने विशेष जांच दल

के काम में देरी से इनकार किया और कहा कि जांच बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ रही है। जाति जगणपना विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गणना से धर्मांतरित लोगों की वर्तमान स्थिति दर्ज की जाएगी। उन्होंने तर्क दिया, अगर समाज समानता और अवसर प्रदान करता तो कोई धर्म परिवर्तन क्यों करता? छुआछूत और भेदभाव ने लोगों को उनके जन्मजात धर्मों से दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मैसूर दशहरा की समावेशी प्रकृति का भी उदाहरण दिया तथा कुछ समुदायों को इस उत्सव का उद्घाटन करने से रोकने की मांग को खारिज कर दिया। अंतर-राष्ट्रीय विवादों पर टिप्पणी करते हुए सिद्धार्थ ने केन्द्र से अलमती बांध की ऊंचाई, महदयों और मेकेदातु परियोजनाओं जैसे मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कुछ भाषणा शासित राज्यों पर न्यायाधिकरण के पूर्व निर्देशों के बावजूद इन मामलों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

विधानसभा में जासूसी के मामले की राज्यपाल को कराई जाने चाहिए जांच : गहलोत

एजेंसी जयपुर
www.dailypioneer.com

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने विपक्ष द्वारा विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे विधायकों की जासूसी करने का आरोप उठाये गये मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि राज्यपाल



मामले में जांच कराई जा
कांग्रेस के वोट चोरी गद्दी
कांग्रेस की बैठक के बाद
यह बात कही। उन्होंने कहा
मामला बहुत गंभीर है और
प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रा
गए हैं और अब राज्यपाल
जांच कराई जानी चाहिये
विधानसभा में दो कैमरा रा
और उनका जो कंट्रोल सि
अपने चैंबर में रखा है, खा
हैं या उनका प्राइवेट सेक्रेट
तो बहुत बड़ा क्राइम किय



जांच होनी चाहिए। उ
राज्यसभा, लोक
विधानसभा में कैमरे
पूरा देश देखता है जब
सिंग के माध्यम से
होती है यूरयूब के म
देख सकते हैं कौन वा
पर अलग कैमरा लगा

तर्फ क्या बात कर रहे हैं वो अ
क्या नहीं कर रहे हैं और पूरा अध
खबर पहुंचती जाए। डोटामरा बा
तो था, सदन स्थगित के समय में
बातचीत होती और किसी भी दल
कोई जुमला बोला देने पर उसे लेक
प्रोसेसिंग में बोला नहीं गया है तब
करवा दो गोविंद सिंह डोटामरा स
एमएलए बनने लायक ही नहीं
करवा दी गई। इस पर सदन में व
पांच साल के लिए निकाल दो, वो
चार साल के लिए निकाल दो, तो
माहौल बनाया गया वह उचित नहीं

**ग्रेटर नोएडा की ऊंची इमारत से
मां-बेटे ने कूदकर की आत्महत्या**

ने कहा कि
ना और
गते हैं और
डियों कॉन्फ्रेंस
जब बहस
में सब
बोल रहा है
विपक्ष की
न के अंदर,
के पास में
मामला यही
पास में जो
न सदस्य हो
को हाउस में
ऐसे कमेट
कि यह तो
और बहस
कह रहा है
कह रहा है
को सदन में
।

बिहार में अधिवक्ताओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए: न्यायमूर्ति सौरेन्द्र पांडे

एजेंसी < मुंगेर
www.dailypioneer.com

पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे ने मुंगेर व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए नवनिर्मित अधिवक्ता हॉल का शुभारंभ किया और कहा कि बिहार में अधिवक्ताओं के बैठने का बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायमूर्ति पांडे ने कहा कि अधिवक्ता जेम्स डिलीवी सिस्टम के एक अभिज्ञ अंग है और उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न केवल मुंगेर बल्कि पूरे देश में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंगेर में अधिवक्ता भवन के निर्माण से अधिवक्ताओं के बैठने की उतम व्यवस्था की गई है। उन्होंने घोषणा की कि वे इम्पेक्टिव जज के रूप में कोशिश करेंगे की कि इस भवन के ऊपर दो मंजिला और भवन का निर्माण हो जिससे कि अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को काम करने की बेहतर सुविधा मिल सके। शुभारंभ के मौके पर अधिवक्ताओं के एक समूह ने न्यायमूर्ति को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मुंगेर के प्रधान जिला एस एन कार्याधीन आलोक गुप्ता, मुंगेर विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष शशि शेखर प्रसाद सिंह के साथ अन्य न्यायाधीश और अधिवक्ता उपस्थित थे। पांडे ने कहा मुंगेर व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता भवन का अधिवक्ताओं को सौंपना एक अच्छी शुरुआत है। इससे पहले मुंगेर विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष शशि शेखर प्रसाद सिंह ने न्यायमूर्ति से मुंगेर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए नवनिर्मित अधिवक्ता भवन के ऊपर दो मंजिला नया भवन बनाने की मांग की थी।

नदी में दो युवक डूबे

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में बनास नदी में नहाने उतरे दो युवक डूब गए। थानाधिकारी राजकुमार नायक ने बताया कि बजरी भरने आए वाहन चालक मोनिस खान (20) निवासी पाण्डरा गढ़ी, वजीरपुर, सवाई माधोपुर और परिचालक मोहित पुजारी (22) निवासी भिघोरा वेर, भरतपुर बनास नदी में नहा रहे थे, तभी गहरे पानी में चले गए और डूब गए। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों की तलाश शुरू की। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है।

महागठबंधन के पास एनडीए की चट्टानी एकता का कोई तोड़ नहीं : उमेश

पटना। बिहार जनता दल यूनाइटेड (जदयू) अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि स्वार्थ की बुनियाद पर खड़े महागठबंधन के पास राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की चट्टानी एकता का कोई तोड़ नहीं है। कुशवाहा ने रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वार्थ की बुनियाद पर खड़े महागठबंधन के पास एनडीए की चट्टानी एकता का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तरीय एनडीए सम्मेलनों में ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे पांचों घटक दलों के कार्यकर्ताओं का उमड़ता सैलाब इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि आगामी चुनाव में विपक्ष की पूरी तरह से सफाया होना तय है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि विकासित बिहार के निर्माण के संकल्प को साकार करने और भावी पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए 2025 में 225 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर नरेन्द्र मोदी-नीतीश कुमार की जोड़ी को मजबूती दें। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से कुमार ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व और विकासोन्मुख नीतियों के माध्यम से बिहार को एक नए स्वरूप में संसार के दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बतोजा। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें गरीबी के बाहर निकालने में कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन यापन में सहूलियत प्रदान कर रहे हैं। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान किया कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता पूरी एकजुटता से बूथ स्तर पर सघन अभियान चलाकर नीतीश सरकार की उपलब्धियों को हर मतदाता तक सही और सटीक रूप में पहुंचाएं।

ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से छात्र की मौत

भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रेली की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुंडा तिराह पर तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्रेली ने एक 18 वर्षीय छात्र राँद दिया। इससे उसकी मौके ही पर मौत हो गयी। घटना के बाद अक्रोशित परिजनों ने अस्पताल द्वार के बाहर राजमार्ग पर जाम लगाकर आरोपी ट्रैक्टर चालक की तुरंत गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। जाम हटाने पहुंचे पुलिस एवं परिजनों के बीच नोकझोंक के बाद तनाव उत्पन्न हो गया। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

चक्की खड्ड में पानी आने के कारण कई गांव फिर से जलमग्न

एजेंसी < होशियारपुर
www.dailypioneer.com

राजबग के होशियारपुर जिले में ब्यास नदी के किनारे बसे कई गांवों के बाढ़ प्रभावित किसानों को नई नुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाँच बांध से लगातार पानी छोड़े जाने और चक्की खड्ड से पानी आने के कारण उनको खेत परफेक्ट से जलमग्न हो गए हैं, जबकि कई परिवार अभी भी अपने क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार रागिनवार सुबह पाँच बांध का जलस्तर 1,390.33 फीट दर्ज किया गया, जो खतरे के स्तर 1,390 फीट की तुलना में थोड़ा ऊपर है। जलाशय में 72,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह हो चुका है, जबकि शाह नहर बैराज में 49,600 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बावजूद, नदी की एक सहायक नदी चक्की खड्ड से लगभग 10,000 क्यूसेक पानी ब्यास नदी



में प्रवेश कर रहा है। जिससे मुकेरियां से लेकर टांडा उप-मंडलों तक कृषि भूमि के बड़े हिस्से फिर से जलमग्न हो गए हैं। कई किसानों ने बताया कि वे जलभराव और कीचड़ भरे रास्तों के कारण अभी भी अपने खेतों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पिछली बाढ़ के बाद से पानी कम नहीं हुआ है। रारा गाँव निवासी मंजीत सिंह (54) ने बताया कि उनका परिवार टांडा-हग्रोबिंदपुर मार्ग पर रारा पुल के पास ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर तिरपाल की चादरों के नीचे दो बड़े बिताने के बाद स

सितंबर को अपने घर लौटा। उन्होंने सरकार की मदद की उम्मीद जताते हुए कहा, हमारे घर और आस-पास की फसलें से भर गए हैं, दीवारें टूट गई हैं और फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमने किसी तरह घर को रखने लायक तो बना लिया, लेकिन छत कमजोर हैं और बारिश में रिसाव रोकने के लिए तिरपाल की चादरों से ढकी हैं। हमारे खेत अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। असली परीक्षा अगर शुरू होती है—फिर से कैसे बचेंगे। राणा गाँव की सड़क के पति चरणजीत सिंह ने बताया कि उनकी 60 एकड़ में से 40 एकड़ जमीन नंदन की पानी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा, बारह एकड़ जमीन पूरी तरह बह गई है जबकि 28 एकड़ जमीन, जिसमें ज्यादातर गन्ना की फसल है, पर तीन से चार फीट तक गन्ना और कीचड़ की मोटी परतें जम गई हैं। गाँव वहाँ कई अन्य लोगों की भी लगभग 50-60 एकड़ जमीन कटाव में चली गई है। खेतों को साफ करने में कम से कम दो साल लगेंगे। 2022 की बाढ़ में भी कुछ खेत गाद से ढँके हुए थे

जिन्हें किसान बहाल नहीं कर पाए हैं, और अब जमीन फिर से दब गई है। उन्होंने आगे बताया कि गाँव में लगभग 8-10 कठों घाह बढ़ गए हैं और कई प्रभावित परिवार किराने के नीचे रह रहे हैं। उन्होंने बताया, जो गांव के लोग हैं वह रेतीली मिट्टी नहीं, बल्कि भारी कीचड़ जिसे सूखने में महीनों लगेंगे और उसके बाद ही उसे हटाया जा सकेगा। ऐसे हालात में आगामी रबी की फसल नहीं बोई जा सकती। पंजाब सरकार की नई नीति जिसका खेत उसकी रेत (जिसका खेत, जमा रेत भी उसकी) का जिक्र करते हुए, चरणजीत सिंह ने कहा कि एक बार गांव सूख जाने के बाद सूखी गाद उठाने के लिए खरीदार मिलने के लिए शूल हो जाता है। उन्होंने कहा, किसानों के बाद ही पता चलेगा कि इसे उन जगहों पर भराव सामग्री के रूप में बेचा जा सकता है या नहीं जहाँ ऐसी मिट्टी की जरूरत है। उन्होंने बताया कि उनके गाँव में लगभग 200 एकड़ जमीन पर ऐसी गाद जमा हो गई है।

झारखंड दौरे पर 15 को आएंगे कांग्रेस प्रभारी के. राजू, संगठन सृजन अभियान को देंगे गति

एजेंसी  रांची
www.dailypioneer.com



अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के स्थायी आमंत्रित सदस्य एकादश झारखंड प्रभारी के. राजू 15 से 21 सितंबर तक सात दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। यह दौरा झारखंड कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान को आगे बढ़ाने और जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक पार्टी को सक्रिय करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने आज बताया कि राजू 15 सितंबर को देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसी दिवस दुमका के संर्याहाट तथा साहबगंज जिले के बरहरवा में

सितंबर को हजारीबाग सर्किटहाउस में उत्तरी छोटानागपुर संभार सरीय बैठक तथा पलामू में जिला अध्यक्षों और पंचवैश्वकों को संभार समीक्षा आयोजित है। अगले दिनांक 19 सितंबर को वे गढ़वा जिला के बड़ाढ़ ब्लॉक में पंचायत समिति का को बैठक करेंगे और रांची में दक्षिण छोटानागपुर संभारिया बैठक में शामिल होंगे। राजू 20 सितंबर को सरायकेला-खरसावां और रांची में मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे। वहीं 21 सितंबर को रांची में अनुसूचित जाति नेताओं तथा खूंटी जिले के कोचांग में स्थानीय आदिवासि समुदाय से मुलाकात करेंगे। उसी रात वे रांची से देहरादून लौटेंगे।

बालको मेडिकल सेंटर ने कार्ट-टी सेल थैरेपी से कैंसर उपचार को दी नई दिशा

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

मध्य भारत में कैंसर उपचार के क्षेत्र में अग्रणी बालको मेडिकल सेंटर (बीएमसी) ने अपने वार्षिक 'छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव' के तीसरे संस्करण से पहले कार्ट-टी सेल और थैरेप्यूटिक अफेरेसिस पर एक विशिष्ट एवं उन्नत कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक हेमेटोलॉजिस्ट्स, ट्रांसप्लूजन मेडिसिन विशेषज्ञ, ब्लड ट्रांसप्लूजन ऑफिसर्स, तकनीकी विशेषज्ञ और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यशाला से इस क्षेत्र में प्रसिजन मेडिसिन और सेल-बेस्ड थैरेपी के नए मानक स्थापित हुए। कार्यशाला का नेतृत्व डॉ. नीलेश जैन (सीनियर कंसल्टेंट एवं हेड, ट्रांसप्लूजन मेडिसिन एवं ब्लड सेंटर) और डॉ. दिव्येंदु डे (सीनियर कंसल्टेंट, हेमेटोलॉजी, हेमेटो-ऑन्कोलॉजी एवं बीएमटी, बीएमसी) ने किया। यह कार्यक्रम डॉ. राजेश देसापांडे, सीनियर मैनेजर, मेडिकल अफेयर्स एवं क्लिनिकल एलीवेशन, फ्रेसीनियस काबी मेडिकल (एशिया पैसिफिक



एवं इंटरनेशनल रीजन) के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रतिभागियों को कार्ट-टी सेल अफेरेसिस, थैरेप्यूटिक अफेरेसिस, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल कलेक्शन और साइटोफेरेसिस की गहन जानकारी और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। सत्र का उद्घाटन करते हुए वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन (बालको मेडिकल सेंटर) की चिकित्सा निदेशक डॉ. भावना सिरौही ने कहा कि बीएमसी, कार्ट-टी जैसी आधुनिक सेल थैरेपी अपनाकर कैंसर इलाज को और बेहतर और युवा डॉक्टरों को सीखने का मौका दे रहा है। यह नवाचार कैंसर मरीजों के लिए

आशा की किरण है। हमारा लक्ष्य है कि बीएमसी को सेल और जीन थैरेपी का प्रमुख केंद्र बनाया जाए, ताकि भारत में कैंसर उपचार को नई दिशा मिले। कार्ट-टी सेल थैरेपी, एक उन्नत इम्यूनोथैरेपी है, जिसमें मरीज के रक्त से टी-सेल्स निकालकर उन्हें जेनेटिक रूप से इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उनसे लड़ सकें। इसका उपयोग जटिल कैंसर, ऑटोइम्यून बीमारियों और रक्त संबंधी विकारों के उपचार में किया जाता है। डॉ. नीलेश जैन ने कहा कि कार्ट-टी सेल थैरेपी कैंसर इलाज में एक नए युग की शुरुआत है। इसमें

अफेरेसिस अहम प्रक्रिया है, जिसके जरिए शरीर की इम्यून कोशिकाओं को अलग कर विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, ताकि वे मरीज को बिल्कुल सही और व्यक्तिगत इलाज दे सकें। डॉ. दिव्येंदु डे ने जोड़ा कि हेमेटो-ऑन्कोलॉजी तेजी से प्रगति कर रही है और यह कार्यशाला ज्ञान साझा करने और वैश्विक विशेषज्ञों से सीखने का एक अवसर है, जो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा। कार्यशाला में मरीज चयन, प्रोटोकॉल्स और पोस्ट-थैरेपी मॉनिटरिंग पर केस-आधारित चर्चाएँ और इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किये गए। इसने बीएमसी की इस



प्रतिबद्धता को और मजबूत किया कि वह चिकित्सा पेशेवरों को ऐसी उन्नत क्षमताएँ और इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता रहेगा, जो परिवर्तनकारी उपचार देने के लिए आवश्यक हैं। वार्षिक 'छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव' के तीसरे संस्करण का आयोजन 19 से 21 सितम्बर 2025 को नया रायपुर स्थित मयफेयर लेक रिजॉर्ट में होगा। इस वर्ष का थीम 'ड्राइविंग कॉमन सेंस ऑन्कोलॉजी' है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनिटोयूरिनरी और लंग कैंसर के मल्टी-डिसिप्लिनरी मेनेजमेंट पर भी विशेष सत्र होंगे। इसमें 10 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और 200 राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल

होंगे। कॉन्क्लेव में पहली बार कई विशेष वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी जिनमें लाइव सर्जिकल डेमोंस्ट्रेशन, मिनी-अर्काईड रिसर्च वर्कशॉप, एसबीआरटी कंट्रिंग ट्रेनिंग तथा जीवन की अंतिम अवस्था में मरीज और परिजनों से संवाद स्किल्स पर सत्र शामिल हैं। इसके साथ ही वीमेन फॉर ऑन्कोलॉजी नेटवर्क मीटिंग और कैंसर प्रिवेंशन वर्कशॉप भी आयोजित होगी। कॉन्क्लेव का रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुका है। इच्छुक प्रतिभागी बालको मेडिकल सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट www.balcomedicalcentre.com पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

फील्ड पर दिखे योजनाओं के काम : अरुण साव

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को हर कार्य की पूर्णता के लिए समय-सीमा तय कर योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने गौधाम योजना के क्रियान्वयन के लिए शीघ्र कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साव ने नगरीय निकायों में निर्माणधीन अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के निर्माण में भी तेजी लाने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक आर. एक्का भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में कहा कि विभाग द्वारा लगातार नवाचार के कार्य किए जा रहे हैं। नवाचारों के साथ ही विभागीय संरचना और योजनाओं का सुदृढीकरण व विस्तारीकरण भी किया जाए।

उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का असर धरातल पर दिखना चाहिए। प्रत्येक कार्य की समय-सीमा तय की जाए। सभी कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही जन सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। साव ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को नगरीय निकायों के सेट-अप पुनरीक्षण और वर्गीकरण के साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय कर स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी निकाय में अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतन देने में विलंब की स्थिति नहीं निर्मित होना चाहिए। समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। साव ने नगरीय निकायों के सभी वाडों में अबादी के हिसाब से समुचित स्ट्रीट लाइटिंग के निर्देश दिए। उन्होंने पार्श्व निधि के तहत इसके प्रावधान का प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने को कहा।

बस्तर संभाग में आदिवासियों की जमीन की खरीदी बिक्री पर लगे रोक : विक्रम मण्डावी

पायनियर संवाददाता < बीजापुर
www.dailypioneer.com

क्षेत्रीय विधायक विक्रम मण्डावी ने बस्तर संभाग में बड़े स्तर पर आदिवासियों के जमीनों की हो रही खरीदी बिक्री पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यपाल को पत्र लिखकर जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। बीजापुर विधायक विक्रम मण्डावी ने महामहिम राज्यपाल को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची में आता है, बस्तर संभाग में आदिवासी वर्ग के लोग आदिकाल से निवासरत हैं। किन्तु वर्तमान में आदिवासियों के जमीनों की खरीदी बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले



नक्सल प्रभावित और अतिसंवेदनशील क्षेत्र है, इन जिलों में भूमिफिया - उद्योगपतियों द्वारा बड़े स्तर पर पैसे का लालच देकर आदिवासियों की जमीनों की खरीदी बिक्री कर लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पैसे के लालच में आकर स्थानीय आदिवासी अपनी पुरतैनी जमीनों को भूमिफियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यदि समय रहते उद्योगपति -भूमिफियाओं को आदिवासियों की जमीन बिक्री करने से नहीं रोका गया तो आदिवासी समाज के लिए भविष्य में विकराल संकट उत्पन्न होगा और दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस कारण बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में आदिवासियों की जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगाना आवश्यक है।

शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगत सिंह में हिन्दी दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम

पायनियर संवाददाता < जगदलपुर
www.dailypioneer.com

जगदलपुर शहर में स्थित भगत सिंह स्कूल में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम हुए प्रारंभ में कक्षा 9वीं के छात्र अनिकेत द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात हिन्दी के व्याख्याता चन्द्र प्रकाश देवांग ने हिन्दी दिवस पर कविता पाठ करते हुए भारतीय हिन्दी जगत के सूर्य कहे जाने वाले भारतेन्दु हरिश्चंद्र एवम् गोस्वामी तुलसीदासजी की कृतियों के संबंध में बताए। स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी के विचारों को बताया। हिंदी के महान कवियों गोस्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीर, रसखान, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेन्दु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी,



रामकुमार वर्मा, जय शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि अनेक रचनाकारों के महाकाव्य और रचनाओं से परिचित कराया गया। कक्षा नवमी के अनिकेत ने हिन्दी साहित्य के इतिहास और उनके साहित्यकारों के नाम बताते हुए हिन्दी भाषा के महत्व को बताया। हिन्दी के व्याख्याता आशा रानी पटनायक ने हिन्दी भाषा को राजभाषा का दर्जा और 14 सितम्बर को संविधान में शामिल किए जाने

और हिंदी भाषा की शुरुआत कैसे हुई इस बात पर जोर दिया। आजादी के पूर्व हमारे कवियों ने अपने वीर रस की कविताओं से जवानों में उत्साह भरते एवं देश भक्ति पूर्ण रचना से लोगों के दिलों में क्रांति पैदा की। ऐसे प्रख्यात कवियों और लेखकों पर अपने विचार व्यक्त किये। कक्षा नौवीं की कुंवारी रिद्धि साहू ने हिंदी दिवस पर सुंदर कविता पाठ किया। संस्था की प्राचार्य

विनीता बेंजामिन ने, पुष्प की अभिलाषा, की कविता का पाठ करते हुए हिंदी भाषा की प्रयोग किए जाने और अधिक हिंदी भाषा को महत्व दिए जाने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन करते हुए हिंदी के व्याख्याता चंद्र प्रकाश देवांग ने राजभाषा मातरम्, हिंदी भाषा मातरम् के गीत के साथ हिंदी दिवस के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की विभागीय समीक्षा बैठक

अंबिकापुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा संभाग के प्रवास के दौरान अंबिकापुर सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री राजवाड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

त्यापारी चुनाव : ओम सोनी पैनल मिला एनएमडीसी किरंदुल के ईडी से, रखीं त्यापारियों की समस्या



पायनियर संवाददाता < किरंदुल
www.dailypioneer.com

लौह नगरी में किरंदुल व्यापारी कल्याण संघ के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। विदित हो कि ओम सोनी पैनल से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश सोनी, उपाध्यक्ष संजय सोनी, सुधमा साहू,कोषाध्यक्ष विशाल जैन,

सचिव राज प्रसाद, सह सचिव शेखर दत्ता, मोहित धवन हैं। ओम सोनी पैनल को चुनाव चिन्ह कलश प्राप्त हुआ है तो वहीं जयदीप माकन पैनल को चुनाव चिन्ह तराजू आवंटित किया गया है। जिसके पश्चात पश्चात ओम सोनी पैनल और जयदीप माकन के पैनलों की टीम ने एवं निर्दलीय प्रत्याशी ने

धुंधाधार प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। इसी तारतम्य में ओम सोनी पैनल ने एनएमडीसी किरंदुल परियोजना के अधिशासी निदेशक रविंद्र नारायण से सौजन्य भेंट करते हुए उनको किरंदुल नगर के व्यापारियों की समस्याओं से अवगत करवाया। जिसका उन्होंने निराकरण करने का आश्वासन दिया।

विज्ञान की जटिल अवधारणाएं सरल और मनोरंजक ढंग से समझेंगे

रायपुर। साइंस पार्क बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। धमतरी जिले का गंगरेल क्षेत्र पहले से ही एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। साइंस पार्क के माध्यम से यहां शिक्षा और पर्यटन का अनेकखा संगम देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य है कि जिले के बच्चे बालिक को केवल किताबी में न पढ़ें, बल्कि उसे छुकर, देखकर और प्रयोग करते समझें। यह पार्क न केवल विद्यार्थियों बल्कि आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए भी एक प्रेरणादायी स्थल बनेगा। साइंस पार्क से आने वाली पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना विकसित होगी, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धमतरी जिले के पं. रविशंकर जलाशय परियोजना गंगरेल स्थित बरूवा गार्डन में साइंस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। गंगरेल जलाशय प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सैलानी और विद्यार्थी भ्रमण के लिए आते हैं।

मितानिन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की रीढ़ है, इसे सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण कदम : श्याम बिहारी जायसवाल

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु 8 सितंबर से आयोजित राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ। यह कार्यशाला पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के एपिडेमियोलॉजी ब्लॉक में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मितानिन कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक, जिला समन्वयक एवं एरिया कोऑर्डिनेटर सहित कुल 36 प्रतिभागी शामिल हुए। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मितानिन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की रीढ़ है, और इसे सशक्त बनाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मितानिन कार्यक्रम को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सामुदायिक



स्वास्थ्य अभियान बताते हुए कहा कि इसे पूरी दुनिया सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य देखभाल के सफल मॉडल के रूप में मान्यता दे चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मितानिन के प्रशिक्षण, मानदेय, उपकरण और डिजिटल साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई दी और कहा कि मास्टर ट्रेनर केवल प्रशिक्षक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक और परिवर्तन के वाहक हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और सामुदायिक सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है। सशक्त मास्टर ट्रेनर समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरी को कम करेंगे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करेंगे। उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे अपने अनुभव साझा करें, निरंतर नवाचार करें और पंचायतों व स्वयं सहायता समूहों के साथ नई विधियों का प्रयोग करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ की शुरुआत हर

गाँव में उस मितानिन से शुरू होती है जो आपके द्वारा प्रशिक्षित और प्रेरित हुई है। इस मौके पर आयुष यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. पी.के. पात्रा, संचालक SIHFW सुरेश पाण्डेय, SACH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.पी. राजेश्वरन और राज्य नोडल अधिकारी डॉ. अजय शंकर कन्नौज भी मौजूद रहे। यह कार्यशाला स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसर्च सेंटर एवं सोसाइटी फॉर एक्शन फॉर कान्युनिटी हेल्थ द्वारा NHM एवं DHS के सहयोग से आयोजित की गई। प्रशिक्षण में विशेषज्ञ डॉ. संजीव उपाध्याय, डॉ. हरीश एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों ने प्रतिभागियों को नई प्रशिक्षण पद्धतियों, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, जागरूकता और कोशल वृद्धि पर मार्गदर्शन दिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना है, जो आगे चलकर ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करेंगे और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाएं।

14 Sep. 2025

Pride Of Raipur

TENSILE SHADE

WE PERSENT ONLY THE BEST

CAR PARK SHADE

WEATHER PROTECTION

Tensile + Membrane + Structure

R. B. Plus

81091 11313

86028 11220

RAIPUR

होमलोन व माईगेज लोन

10 लाख से 10 करोड़ तक

राष्ट्रीयकृत एवं प्रतिष्ठित बैंक द्वारा

होम लोन ब्याज दर मात्र 7.35%*

माईगेज लोन ब्याज दर मात्र 8.75%*

वर्तमान होमलोन को टुंसापकर कराएँ | पायें उनका ही अतिरिक्त लोन, कम ब्याज दर पर 7.35%*

होम लोन दर पर 8.70%*

SHRI SIDDHI VINAYAK FINACE

Near Samudayik Bhawan, Jorapara, Raipur

Mob.: 9329002356

नोट - बैंकिंग एवं फायनेंस सेक्टर में कार्य करने हेतु अनुभवी तज्ज्ञों की आवश्यकता है।

हिप्नोसिस

● पूर्व जन्म ट्रेनिंग

● मानसिक असुधार से मुक्ति

● किसी भी प्रकार का तनाव चिंता रिश्ते की समस्या

● ऐसा लगता है कि कोई है साथ में पर वो सिर्फ डर है खुद का

● अवस्था की चिंता

ऐसे सभी कारणों का निदान संभव है हिप्नोसिस के द्वारा

S. Nitin

Astrology & Numerology Expert

प्रमाणित और उच्च प्रशिक्षित सल्लेजियन डिप्लोमा प्राप्त और रायपुर एडमिनिस्ट्रेशन

www.snitinnumerological.com

7000074769

वुडन आर्ट एण्ड फर्नीचर

(विगत 29 वर्षों से स्थापित संस्थान)

■ त्रिपुरा का बांस फर्नीचर

■ आसाम का बेंत फर्नीचर

■ बस्तर का आदिवासी- सागौन फर्नीचर

■ सहारनपुरी पार्टीशन

www.bastaria.com

9425212830

M A K AZAD COLLEGE OF PHARMACY RAIPUR

(Approved/ Affiliated-CSVU-DTE-PCI)

SANTOSHI NAGAR MATHPURENA, RAIPUR (C.G.)

रायपुर शहर में स्थित एक मात्र कॉलेज

D.PHARMA

B.PHARMA

B.PHARMA (Lateral Entry) (2nd Yr. Direct Admission)

(THE ONLY COLLEGE IN RAIPUR CITY) HOSTEL/SCHOLARSHIP FACILITY

एडमिशन के लिए संपर्क करें या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें

www.makazadpharmacy.com

CONTACT FOR ADMISSION OR REGISTRATION

0771-4913335, 9425214413, 9329621221

अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज्यपाल द्वारा सम्मानित और कई अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलनों में सम्मानित

ज्योतिषाचार्य पं. देवेश पण्डा (शास्त्री)

ज्योतिषाचार्य वास्तु शास्त्री ट्रेड कोर्स रीटर्न कर विजेता

यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो दिखें गये नंबर पर संपर्क करें

+91-9474170000

निवास- आर 11 रोड 1 गिरधरजी नगर रायपुर | कार्यालय- मोटेन किंग लॉन्गवे फार्म रायपुर नं. 10-11 बीजेपी कॉम्प्लेक्स एलान पुरी, तत्वच भवन, रायपुर

astrologer pandit devesh panda

अजय श्री कृष्ण

अंकित बाउण्डीवॉल

प्रिकास्ट

वेनलिक जाली

पॉल फेंसिंग

अब आपके वेशकीमती प्लाट को सुरक्षित रखना हुआ आसान

प्रिकास्ट, सिक्स बाउण्डीवाल, डी.पी. सी पोल फेंसिंग करवाने हेतु संपर्क करें ।

V.I.P. रोड रायपुर

98279-59655

Cartridge Refilling

Refilling @ Your Door Step

JB Mall, Lower Ground Floor, M.G. Road, Raipur (C.G.)

Callaway

Print Your Omagination With Us.

9302787900, 9425211789

विज्ञापन के लिये संपर्क करें : 9827146567, 9329846567

भाजपा सरकार बिजली कीमतों में बढ़ोतरी वापस ले : डॉ. महंत

सितंबर माह में प्रत्येक घरेलू बिजली उपभोक्ता पर कम से कम 1000 का अतिरिक्त भार

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी ने आम जनता के साथ-साथ राज्य के किसानों की भी कमर तोड़ दी है। इस वृद्धि ने घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, कृषि क्षेत्र को सीधे प्रभावित किया है, जिससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ऊर्जा विभाग स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। प्रदेश में ऊर्जा विभाग के वर्तमान आकड़े अनुसार एकल बत्ती कनेक्शन 15-लाख 16-हजार 283, कृषि पम्प

कनेक्शन 5-लाख 94-हजार 277, एल.टी.(घरेलू) कनेक्शन 63-लाख 45-हजार 448, एच.टी (व्यवसायिक) कनेक्शन 3-हजार 8-सौ 99 है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, यह वृद्धि तब हुई है जब छत्तीसगढ़ कोयला और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। हम न केवल अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि इन संसाधनों की आपूर्ति दूसरे राज्यों को भी करते हैं। ऐसे में बिजली मूल्य वृद्धि का कोई ठोस कारण नहीं दिखता, महंगाई के इस दौर आम जनता आर्थिक बोझ से परेशान है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा हमारी 'बिजली हाफयोजना' को बद करने



से जनता पर आर्थिक बोझ की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ रियायती योजना को लगभग खत्म कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों और किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, बिजली दरों में लगातार हो रही वृद्धि ने घरेलू बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है और छोटे व्यवसायों की लागत कई गुना बढ़ गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। इस अप्रत्याशित वृद्धि से आम नागरिकों में भारी असंतोष है, क्योंकि उनकी दैनिक जीवन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर बिजली पर निर्भर हैं। बिजली की बढ़ती कीमतें सीधे तौर पर उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि कर रही हैं, कई छोटे और सीमांत किसान अब

अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बिजली का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी पैदावार और आजीविका पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यह स्थिति न केवल किसानों की आर्थिक स्थिरता को चुनौती देती है, बल्कि राज्य की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, सरकार बढ़ी हुई बिजली दरों को तुरंत वापस ले। किसानों के लिए कृषि पंपों पर विशेष सब्सिडी या रियायती बिजली दर लागू करें। किसानों के लिए कृषि पंपों पर विशेष सब्सिडी या रियायती बिजली दर लागू करें। राज्य में बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी वृद्धि को रोका जा सके।

प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सुशील शर्मा ने नगर पालिका के अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप



पायनियर संवाददाता < भाटापारा
www.dailypioneer.com

प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि एवं पूर्व मंत्री अध्यक्ष सुशील शर्मा ने नगरीय निकाय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में निर्माणाधीन विभिन्न बाड़ों में 15 वे वित्त आयोग से आरसीसी नाली निर्माण सहित 56 लाख रूपिये की लागत वाले चर्च से रेलवे क्रासिंग तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य को वर्षा ऋतु में शुरू कराकर नियमों का खुल्लेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि उस कार्य को महज 20 से 25 लाख की लागत में ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। शर्मा ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में सीएमओ, इंजीनियर, सहायक यंत्री सहित निर्माण एजेंसी की मिलीभगत है, जो भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार कर सरकारी धन का



दुरुपयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार वर्षा काल में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहता है। इसके बावजूद बार-बार निर्देशों की अनदेखी कर नगरीय निकाय के अधिकारियों ने कार्य प्रारंभ करवा दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जिस स्थल पर नाली बनाया जा रहा है, वहां वर्तमान में पानी का बहाव नहीं है। आरसीसी नाली निर्माण कराने का कार्यदेश देने वाले नगर पालिका के लोक निर्माण विभाग से संबंधित अधिकारियों ने कार्य प्रारंभ करने से पहले निर्माण एजेंसी के दुबारा उपयोग में लाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि यह पूरा कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने जा रहा है। सुशील शर्मा ने इस मामले की शिकायत संचालक सचिव नगरीय प्रशासन, लोक आयोग और राज्यपाल से की है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने हेतु कड़ी कार्रवाई करते हुये निस्सहज जाँच कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इंजीनियर, सहायक यंत्री को तत्काल निलंबित किया जाये।

कवर्धा में बनने जा रही नालंदा लाइब्रेरी, 4.37 करोड़ की स्वीकृति

कलेक्टर ने स्थल का किया निरीक्षण

पायनियर संवाददाता < कवर्धा
www.dailypioneer.com

कबीरधाम जिले के युवाओं का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। दिल्ली और रायपुर की तर्ज पर कवर्धा में बहुप्रतीक्षित नालंदा लाइब्रेरी के निर्माण की राह साफ हो गई है। राज्य शासन से इसके लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने छोरपानी कॉलोनी स्थित जिला परिवहन कार्यालय के समीप प्रस्तावित स्थल



का निरीक्षण किया। यहां मौजूद पुराने जर्जर भवनों को तोड़ने के निर्देश दिए गए। अभी इस भवन में आबकारी

विभाग का कंट्रोल रूम संचालित हो रहा है, जिसे अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में नई सौगात

कबीरधाम जिले में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई सौगातें मिल रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहले से संचालित भोरमदेव शिक्षा पीठ कोचिंग संस्थान युवाओं को लाभ पहुंचा रहा है। दिल्ली एकेडमी द्वारा चलाए जा रहे इस संस्थान से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। नालंदा लाइब्रेरी और भोरमदेव शिक्षा पीठ मिलकर कवर्धा को शैक्षणिक उत्कृष्टता की नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे। अब युवाओं को तैयारी के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करने की जरूरत नहीं होगी।

भूमिपूजन करेंगे उपमुख्यमंत्री

नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश चन्द्रवंशी ने बताया कि लाइब्रेरी का भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर बी.आर. देवांगन, एसडीएम चेतन साहू, तहसीलदार परमेश्वर मंडवी और सीएमओ भी मौजूद रहे।

आधुनिक स्वरूप में होगी लाइब्रेरी

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नालंदा लाइब्रेरी का मॉडल भी देखा। यह लाइब्रेरी तीन मंजिला भवन के रूप में तैयार होगी। इसमें 200 सीटर वातानुकूलित हॉल होगा, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को कि-बुक सुविधा मिलेगी। कलेक्टर ने कहा कि नालंदा लाइब्रेरी कवर्धा सहित पूरे जिले के लिए ज्ञान, अध्ययन और प्रतियोगी शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगी।



कार्यक्रम के प्रथम समारोह यादव शिरमणि गौरव सम्मान, जो कि 21 सितम्बर को होगा, की जानकारी दे उन्हें आमंत्रित किया। ज्ञात हो कि यह आयोजन यादव महासंघ और संगठन

को मजबूती देने वाले 32 दिवंगत आजीवन सदस्यों की स्मृति में संपन्न होने वाला है। इस अवसर पर सुभाष राठी एवं अनिल अग्रवाल भी उपस्थित थे।

गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय मे एल्युमिनी मीट का आयोजन



पायनियर संवाददाता < भाटापारा
www.dailypioneer.com

गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय भाटापारा में एल्युमिनी मीट आयोजित किया गया। जिसमें भूतपूर्व विद्यार्थियों ने अधिक संख्या में उपस्थित होकर न केवल

कार्यक्रम की महिमा बढ़ाई बल्कि महाविद्यालय के प्रति अपना प्रेम और समर्पण भी व्यक्त किया। 2014 से 2024 तक के पूर्व विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में व्यतीत किए अपने समय को

याद किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ रीता दीवान प्राध्यापक डॉ निधि मिश्रा, एल्युमिनी मीट के संयोजक डॉ राम आशीष श्रीवास्तव की उपस्थिति में यह सम्मेलन बड़े ही हर्षोल्लास से भरे हुए माहौल में संपन्न हुआ।

गौमाताओ एवं बछड़ों को रेडियम बेल्ट लगाया गया एवं घायल सांड का उपचार

पायनियर संवाददाता < भाटापारा
www.dailypioneer.com

अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, ग्रेन सिटी शाखा भाटापारा के तत्वावधान में गौ माता के लिए रेडियम बेल्ट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य रात के समय सड़कों पर विचरण करने वाली गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तीन चरणों में तीन दिवसीय यह कार्यक्रम क्रमशः तरंगा रोड, देवरीरोड तथा बलौदाबाजार रोड में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक कार चालक



द्वारा सांड को बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। सूचना मिलते ही भाटापारा गौ सेवक भाई अभिषेक मिश्रा एवं उनके साथियों को सूचित कर त्वरित उपचार प्रदान किया गया।



साथ ही घायल सांड को भी रेडियम बेल्ट पहनाया गया ताकि भविष्य में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में मंच के प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रशांत गांधी, शाखा अध्यक्ष

कैलाश बंसल, कोषाध्यक्ष अभिषेक टाटिया, उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, सहसचिव भावेश अग्रवाल, सिद्धार्थ गोलछा सहित अन्य सदस्य गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की पूरी

गरियाबंद जिले में गौधाम बनाने की प्रक्रिया तेज

पायनियर संवाददाता < देवभोग
www.dailypioneer.com

गरियाबंद जिले के पांचों विकासखंड छुरा, फिंगेश्वर, गरियाबंद, मेनपुर तथा देवभोग अंतर्गत प्रथम चरण के गौधाम बनाने हेतु विकासखंडवार 10-10 गौठानों का चयन किया जा रहा है। इन चयनित गौठानों में उपलब्ध संसाधनों जैसे बाड़ड़ीवाल, फेंसिंग, जल एवं विद्युत आपूर्ति, बाड़ा/ पशु शेड आदि की उपलब्धता की सूची राज्य गौसेवा आयोग को भेजी गई है। गौधामों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गरियाबंद के कलेक्टर भगवान सिंह उडके द्वारा पशुधन विकास विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की विशेष बैठक लेकर पशुधन विकास विभाग जिला गरियाबंद के उपसंचालक डॉ. ओपी तिवारी को इस कार्य में गति लाने के निर्देश दिए गए थे जिसके परिपालन में चयनित गौठानों की सूची छत्र राज्य गौसेवा आयोग को भेजने के उपरांत जिला एवं विकासखंड स्तरीय जिले के विकासखंड गरियाबंद से 02, विकासखंड देवभोग से 02 तथा विकासखंड मेनपुर से 03 आवेदन सहमति के आधार पर प्राप्त हुए हैं।

को प्राथमिकता के आधार पर गौधाम संचालन का दायित्व सौंपा जाना है। इसके अलावा एनजीओ, किसान उत्पादक संगठन एवं अन्य पंजीकृत संस्थाएं तथा स्वसहायता समूह आदि उनके सहमति के आधार पर पात्र होंगे। गौधाम संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं को सहमति के अनुरूप आवेदन करने के लिए विकासखंड के पशु चिकित्सालयों, कृत्रिम गर्भधान केंद्र, मुख्य ग्राम खंड से निर्धारित पात्र प्राप्त कर आवेदन किए जाने की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक संस्थाएं इन विभागीय संस्थानों से आवेदन के प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। गौधाम संचालन हेतु प्राप्त आवेदन कलेक्टर के माध्यम से छत्र राज्य गौसेवा आयोग को प्रेषित किए जायेंगे जहाँ से गौधामों के अंतिम चयन की प्रक्रिया अपेक्षित मापदंडों के अनुसार किया जायेगा। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक गौधाम संचालन हेतु जिले के विकासखंड गरियाबंद से 02, विकासखंड देवभोग से 02 तथा विकासखंड मेनपुर से 03 आवेदन सहमति के आधार पर प्राप्त हुए हैं।

सड़कों के सुदृढ़ीकरण को मिली मंजूरी, भाजपा जिलाध्यक्ष ने सीएम और विभागीय मंत्री का जताया आभार



पायनियर संवाददाता < बालोद
www.dailypioneer.com

भाजपा के जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख एवं जिले के नेताओं द्वारा हाल ही में बालोद जिले के खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण को लेकर उठाई गई मांगें अब पूर्ण हो गई हैं। यह मांगें तब सामने आई जब छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री विजय शर्मा का बालोद दौरा हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला

स्वीकृत सड़कों की सूची
लाटाबोड से देवी नवागांव- 3.10 किमी, डोंडी से कोपेडेरा- 9.25 किमी, गुरुर से नारागांव- 32.10 किमी, भाटागांव से पायला- 4.60 किमी, मेन रोड (एसएच-5) से नेवारीकला- 2.55 किमी, पीचेटोला जबकसा से नरंगलपुड़ा- 2.20 किमी, मेन रोड (टी-07) से चिखल्ली- 2.60 किमी, केरी जूंगरा जामड़ी से पाटेस्वर धाम- 4.60 किमी।

कार्यालय में आयोजित बैठक में जिले के नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की दयनीय स्थिति की जानकारी दी और ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। मंत्री विजय शर्मा ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। अब, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चयनित सड़कों के सुदृढ़ीकरण (सतह मजबूतीकरण) हेतु वित्त

विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृत सभी मार्गों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में अब राहत मिलेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख, नेता, जनप्रतिनिधि एवं समस्त कार्यकर्ताओं ने इस स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

स्कूली बच्चों संग सरपंच चंद्रिका साहू ने मनाया जन्मदिन



पायनियर संवाददाता < पाटन
www.dailypioneer.com

ग्राम पंचायत तरीघाट की सरपंच चंद्रिका साहू ने अपना जन्मदिन सादगीपूर्ण और अनूठे तरीके से मनाया। उन्होंने शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला तरीघाट में बच्चों के साथ बैठकर न्योता भोज किया और इस खास मौके पर बच्चों को खीर-पूरी परोसी गई। सरपंच ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया और उन्हें अतिरिक्त पोषण आहार के

महत्व के बारे में भी बताया। इस पहल से नन्हें-मुन्ने बच्चों के चेहरे खिल उठे और स्कूल का माहौल उत्साहपूर्ण हो गया।

शासन की मंशा के अनुरूप पहल
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधि अपने जन्मदिन व विशेष अवसरों पर बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराते हैं। इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होता है, बल्कि समुदाय की भागीदारी भी बढ़ती है।

न्योता भोज का उद्देश्य
बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराना। समुदाय में सामाजिक सौहार्द और एकता को बढ़ावा देना। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने विशेष अवसरों को समाज हित में समर्पित करना।

गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी
कार्यक्रम में उप सरपंच प्रकाश गोस्वामी, स्कूल प्रबंधन अध्यक्ष रोहित बन गोस्वामी, शेष नारायण सिन्हा, सुरेश कुमार निषाद, नारायण, चेला राम सिन्हा, संजु साहू, राकेश साहू, शिक्षक लोकनाथ सोनवानी, ऋषि कुमार साहू, कविता मीरे सहित रसोइया और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं, पत्रकार संतोष देवांगन, प्रेस क्लब अमरेश्वर के अध्यक्ष करन साहू तथा रिपोर्टर खिलेश साहू भी सरपंच को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे।

निगम आयुक्त के खिलाफ पार्षदों का मोर्चा, विधायक को सौंपा ज्ञापन

पायनियर संवाददाता < भिलाई
www.dailypioneer.com

नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा में इन दिनों पार्षदों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद एकजुट होकर निगम आयुक्त डी.एस. राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सभी पार्षदों ने अहिवारा विधायक डोमनलाल कोसेरवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर आयुक्त को हटाने की मांग की। ज्ञापन में पार्षदों ने लिखा है कि आयुक्त डी.एस. राजपूत किसी भी पार्षद के आवेदन पर विचार

नहीं करते। शहर की समस्याओं का निराकरण तक नहीं किया जा रहा है। पार्षदों का आरोप है कि आयुक्त द्वारा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की घोर अनदेखी की जा रही है। न तो नालियों की सफाई होती है और न ही अन्य सार्वजनिक कार्य समय पर पूरे किए जाते हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयुक्त पार्षदों के फोन तक रिसीव नहीं करते। लगातार कॉल करने के बाद भी उनसे संपर्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। पार्षदों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयुक्त बिना कमीशन लिए कोई भी कार्य

नहीं करते। यदि किसी काम में कमीशन तय नहीं होता तो वह फाइल लंबित रख दी जाती है और पैसों की मांग जारी रहती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि आयुक्त का निगम कार्यालय में रहना भी तय नहीं है। कई बार वह केवल आधा घंटा ही ऑफिस में बैठकर चले जाते हैं। पार्षदों ने विधायक से स्पष्ट कहा है कि ऐसी कार्यप्रणाली के चलते जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए आयुक्त डी.एस. राजपूत को तत्काल पद से हटाया जाए।

नहीं करते। यदि किसी काम में कमीशन तय नहीं होता तो वह फाइल लंबित रख दी जाती है और पैसों की मांग जारी रहती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि आयुक्त का निगम कार्यालय में रहना भी तय नहीं है। कई बार वह केवल आधा घंटा ही ऑफिस में बैठकर चले जाते हैं। पार्षदों ने विधायक से स्पष्ट कहा है कि ऐसी कार्यप्रणाली के चलते जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए आयुक्त डी.एस. राजपूत को तत्काल पद से हटाया जाए।



संपादकीय

क्रास वोटिंग विवाद का विषय

इन दिनों, राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे सहज और दोषरहित कहा जा सके। हाल ही में हुआ उपराष्ट्रपति चुनाव भी इसका अपवाद नहीं है। एनडीए उम्मीदवार ने भले ही अच्छे अंतर से जीत हासिल की हो, लेकिन सत्ता के गलियारों में क्रॉस-वोटिंग और खरीद-फरोख्त के आरोप अभी भी चर्चा में हैं। उपराष्ट्रपति का पद काफी हद तक औपचारिक होता है। गुप्त मतदान से तय होता है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। हालाँकि यह एक औपचारिकता है, लेकिन यह शक्ति और एकता के प्रदर्शन के साथ-साथ अन्य जगहों पर होने वाले आगामी चुनावों का पुर्नार्भस भी हो सकता है।

भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के चुनाव ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें विपक्षी सांसदों द्वारा क्रॉस-वोटिंग के आरोप चुनाव के बाद की चर्चाओं में छाप हुए हैं। जहाँ भाजपा इस जीत का जश्न रूएक विनम्र और कुशल देशभक्तर के लिए जनादेश के रूप में मना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आंतरिक एकता और विश्वसनीयता के सर्वालों से जुझ रही है। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले - एनडीए के कुल 438 सांसदों (वाईएसआर काग्रिस के 11 सांसदों के समर्थन सहित) से 14 ज्यादा। इसके विपरीत, विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट ही मिले, जबकि विपक्षी दल ने 315 सांसदों के समर्थन का दावा किया था।

इस विसर्गति ने तुरंत क्रॉस-वोटिंग की आशंकाओं को जन्म दिया, जो 15 मतपत्रों के खारिज होने से और बढ़ गई। काग्रिस नेता मनीष तिवारी ने इस घटनाक्रम को रश्वास का गंभीर उल्लंघनर् बताया। चूँकि उपराष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान



के माध्यम से होता है और पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, इसलिए तकनीकी रूप से सांसद अपनी अंतराला की आवाज पर मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

फिर भी, व्यवहार में, सांसद शायद ही कभी पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हैं - जिससे कथित क्रॉस-वोटिंग बिहार और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से पहले विपक्ष के लिए विशेष रूप से नुकसानदेह साबित हो रही है। नुकसान की भरपाई के लिए, विभिन्न भारतीय ब्लॉक दलों के नेताओं ने किसी भी विश्वासघात से इनकार करने की कोशिश की। राजद के तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी के सभी नौ सांसदों ने गठबंधन उम्मीदवार का समर्थन किया था, जबकि तृणमूल काग्रिस नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि वोट खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया, जबकि उन्होंने कहा कि सभी 41 तृणमूल सांसदों ने विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन किया।

इस रहस्य को और बढ़ाते हुए, 15 में से सात अवैध वोटों में भी यही पैटर्न देखा गया: एनडीए उम्मीदवार के लिए चिह्नित मतपत्र, लेकिन गलत तरीके से डाले गए। दो पर सही का निशान था, और एक पर कोई आकृति लिखी हुई थी - जिससे जानबूझकर की गई तोड़फोड़ का संदेह पैदा होता है।

विपक्ष के लिए, इस घटना ने एकजुट मोर्चे के रूप में पेश की जा रही छवि में दरार को उजागर कर दिया है। भाजपा के लिए, यह मनोबल बढ़ाने वाला है जो एक विखंडित विपक्ष के उसके उस कथन को पुष्ट करता है जो एकजुट कार्रवाई करने में असमर्थ है। राज्य चुनावों के मँडराते हुए, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस-वोटिंग को लेकर विवाद संसद की दीवारों से परे भी गूँजे की संभावना है। लेकिन अंतरः, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नुकसान है, जहाँ हर चुनाव संधिध हो जाता है, और सांसदों का आचरण - साथ ही आरोप-प्रत्यारोप - उड़ते हैं, जिससे धन-बल और कदाचार की भूमिका को हवा मिलती है।

कहां तक पहुंची हिंदी राजभाषा राष्ट्रभाषा या वैश्विक भाषा ?



डॉ राजाराम त्रिपाठी
स्वतंत्र स्तंभकार

हिंदी दिवस के बहाने हर साल हम सब उसी पुराने झुनझुने को बजाते हैं, हिंदी हमारी आत्मा है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी की जय हो। और अगले ही पल फाइलें, आवेदन पत्र, आदेश और अदालती कार्यवाही अंग्रेजी में ही चलती रहती हैं। यह वही स्थिति है, जिसे कवि भवानीप्रसाद मिश्र ने बरसों पहले कहा था, हिंदी का दुखड़ा कोई सुनता नहीं, और गाता हर कोई है।

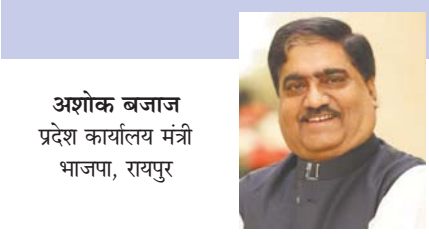
भारत की इस दुविधा पर याद आता है संस्कृत वचन - मातृभाषा न त्याज्या कदापि अर्थात मातृभाषा कभी भी त्यागने योग्य नहीं। लेकिन हम भारतीय शायद अपवाद साबित होने पर ही गर्व करते हैं।

आंकड़े चीखते हैं, पर हम बहरे हैं - भारत में 46 करोड़ लोग हिंदी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। विश्व स्तर पर हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ से अधिक मानी जाती है। गूगल की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की हिस्सेदारी केवल 0.1%

है, जबकि अंग्रेजी का हिस्सा 55% से अधिक है। शिक्षा मंत्रालय के आँकड़े कहते हैं कि उच्च शिक्षा के 85% से अधिक शोधपत्र आज भी अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। ज्ञान यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हिंदी ज्ञान-विज्ञान और तकनीक की भाषा क्यों नहीं बन पा रही? **राजभाषा, पर राज किसी और का** - हिंदी 1950 से भारत की राजभाषा घोषित है। पर सच्चाई यह है कि संसद, न्यायालय, विश्वविद्यालय और बड़े वैज्ञानिक संस्थान अभी भी अंग्रेजी की दसता से मुक्त नहीं हुए। क्या यह विडंबना नहीं कि देश का प्रधानमंत्री हिंदी में बोलता है, पर उसी के मंत्रालयों के आदेश अंग्रेजी में लिखे जाते हैं? यह वही दोमुँही स्थिति है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था— राजभाषा हिंदी है, पर राज अंग्रेजी करता है।

दुनिया से सीखने की जरूरत - यहाँ पर मुझे अपने हाल की रूस यात्रा का अनुभव जोड़ना होगा। हर तरफ से साधन-संपन्न होने के बावजूद रूस ने तमाम वैश्विक दबाव और आंतरिक कठिनाइयों के बीच अपनी भाषा पर अटूट विश्वास रखा है। विज्ञान हो या परमाणु तकनीक, साहित्य हो या अर्थशास्त्र, हर विषय की पढ़ाई-लिखाई वे अपनी ही भाषा में करते हैं। इसी तरह जर्मनी और फ्रांस तो भाषा-गौरव के लिए पहले से विख्यात हैं। किंतु मैंने अपनी यात्राओं के दौरान यह भी देखा कि थाईलैंड और कंबोडिया जैसे छोटे देश, और यहाँ तक कि इथियोपिया जैसा सबसे गरीब माने जाने वाला देश भी, अपना सारा शासकीय कामकाज और शिक्षा अपनी भाषा में ही करते हैं। और हम? हम अभी भी सोचते हैं कि हिंदी में विज्ञान पढ़ाने से छत्र कमजोर हो जाएँगे!

जीएसटी दरों में अप्रत्याशित कटौती से कृषि बाजार होंगे गुलजार



अशोक बजाज
प्रदेश कार्यालय मंत्री
भाजपा, रायपुर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दूर दृष्टि सोच के तहत जी.एस.टी. दरों में भारी भ्रक्क कटौती की है। इस कटौती का सीधा लाभ कृषि एवं किसानों को मिलेगा। 22 सितम्बर 2025 से लागू होने वाली नई दरें कृषि व कृषकों के कल्याण के लिए एक का पथर साबित होगी। भारत सरकार के फैसले से सीक तरफ जहां कृषि लागत मूल्य कम होगा तो वहीं उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि होगी। इससे किसानों की बल्ले-बल्ले तो होगी ही साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनने तथा

विकसित भारत की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने का अवसर मिलेगा।

भारत में जी.एस.टी. (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) एक एकीकृत टैक्स व्यवस्था है जो वेट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित कर 1 जुलाई 2017 से लागू है। देश में व्यापार को सुलभ बनाने, पारदर्शिता लाने एवं कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से लागू इस व्यवस्था में वर्तमान मे चार स्लेब हैं जिसे घटकर अब दो स्लेब कर दिया गया है। जनता की मांग पर व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के हित में 2017 के बाद कई बदलाव हुए हैं लेकिन जी.एस.टी. कौंसिल की 56वीं बैठक में जो बदलाव का निर्णय लिया गया है वह नई आर्थिक क्रांति का सूचक है। 22 सितम्बर 2025 से लागू होने वाली नई व्यवस्था तथा जी.एस.टी. दरों में कटौती से आम उपभोक्ताओं विशेष कर किसानों के लिए सौगत से कम नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में उपयोग में आने वाली मशीनों, उपकरणों, थ्रेसर, खाद्यान्न प्रोसेसिंग उपकरण, खाद निर्माण

की मशीनों, जैव-कीटनाशक, वानिकी व बागवानी के उपयोग की मशीनें व उपकरण, सिंचाई के काम में आने वाली मशीनें, ड्रिप एरिगेशन सिस्टम, स्पिंकलर, डेयरी उद्योग व पशुपालन, मुर्गीपालन, बकरी पालन व मत्स्य पालन में उपयोग की जाने वाली मशीनों और उपकरणों के अलावा अन्य कृषियोगी यंत्रों के दाम सस्ते हो जायेंगे। वर्तमान में इन पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था जो घटकर अब मात्र 5 प्रतिशत हो जायेगा। फलस्वरूप किसानों को सस्ते दामों पर उपकरण बाजार में मिलेंगे। इन उपकरणों के सस्ते हो जाने से इन मशीनों की मांग बाजार में बढ़ेगी जिससे उपकरण निर्माण से जुड़े उद्योगों को भी फायदा होगा। कृषियोगी यंत्रों के दाम घटने से लघु व सीमांत किसान भी इन उपकरणों का इस्तेमाल कर सकेंगे। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग बढ़ेगा। किसानों को कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करने की हमेशा चिंता रहती है, जी.एस.टी. दरों में प्रस्तावित कटौती से उनकी यह चिंता दूर हो जाएगी। नए बदलाव से उत्पादन लागत तो घटेगा ही, साथ ही साथ नई उन्नत तकनीक के प्रयोग से कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा।

हिंदी आज भी मंच की शेरनी है और दफ्तर की बकरी, जो नेता इसके नाम पर गरजते हैं, और सचिवालय में वही अंग्रेज़ी की दुम हिलाते रहते हैं



भोदी सरकार ने चमत्कारिक निर्णय लेते हुए 12 किस्म की जैव-कीटनाशकों और प्राकृतिक मेंधाल पर भी टैक्स घटा दिया है जिससे भारत में जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में किसानों को कृषि उत्पाद के विपणन के लिए सुलभ बाजार की व्यवस्था तो है ही, लेकिन लघु एवं सीमांत किसान साधन के अभाव में अपना उत्पाद बाजार तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। अब संसाधनों के मूल्य में कमी हो जाने से अपने उत्पादों को परिवहन करके बाजार तक आसानी से पहुँचा सकेंगे। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी.एस.टी. दरों में कटौती करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। निश्चित रूप से इस बदलाव से कृषि प्रधान देश में आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 22 सितम्बर 2025 का दिन भारत के खेती किसानी के लिए स्वर्णिम युग की शुरुवात होगी। इस ऐतिहासिक बदलाव से खेत और खेतिहर दोनों गुलजार होंगे।

है। उदाहरण के तौर पर, 2004 के एच-1बी वीजा सुधार अधिनियम ने वेतन स्लेब का पुनर्गठन किया और दो वेतन स्तर डाले, एक क्षेत्र में किसी व्यवसाय के लिए सर्वेक्षण किए गए कुल वेतन के 34वें और 50वें प्रतिशतक पर, उच्चतम (67वें प्रतिशतक) से नीचे। तीसरा, उनके आकर्षक वेतन पैकेज में ई-एसओपी और अन्य वेरिगबल्स शामिल होते हैं जो वास्तव में उन्हें मिलने वाली राशि का हिस्सा नहीं होते, और विदेश में रहने का खर्च भारत में रहने के खर्च से काफी ज्यादा है। किराया, किराने का सामान और यात्रा, ये सभी उनके खर्च का एक बड़ा हिस्सा हैं, और जो बचता है वह उनके परिवारों को वापस भेज दिया जाता है। हालाँकि आइवी लीग संस्थानों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्र शायद भारत में नहीं रुकना चाहेंगे, लेकिन कई अन्य लोगों को यहीं रोकना आसान काम होगा। कम से कम प्रयासों से, भारत प्रतिभाओं को बनाए रखने में सक्षम होगा जो न केवल आने वाले वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में दिखाई देंगे, बल्कि इस प्रक्रिया में अनुसंधान एवं विकास को भी आगे बढ़ाएंगी। सहयोग का एक विशेष रूप से आशाजनक क्षेत्र शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भारत और यूएई के बीच बढ़ती साझेदारी है। यूएई भारतीय पेशेवरों के लिए एक शीर्ष गंतव्य बन गया है, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों के लिए अवसरों का विस्तार हो रहा है। शिक्षा के लिहाज से, दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए सहयोगी कार्यक्रमों, आदान-प्रदान पहलों और छात्रवृत्तियों की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान संयुक्त

अरब अमीरात में अपने परिसर स्थापित कर रहे हैं, जिससे संबंध और मजबूत हो रहे हैं। भारतीय छात्रों के लिए, यह विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए एक आकर्षक और नजदीकी विकल्प प्रदान करता है, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रोजगार की बेहतर संभावनाएं भी प्रदान करता है।

भारत में प्रतिभाओं को बनाए रखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, अधिक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करना और दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि विदेश से स्नातक करने के बाद भारतीय अपने देश लौट आएँ। दूसरे उद्देश्य के संदर्भ में, भारत पहले से ही प्रतिभा पलायन को रोकने की प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, प्रमुख वैश्विक विश्वविद्यालयों से पीएचडी प्राप्त भारतीय छात्रों के नेतृत्व में सबसे अत्याधुनिक, डीप टेक और अग्रणी टेक स्टार्ट-अप अब भारत में जड़ें जमा रहे हैं। हमारे स्टार्ट-अप एक दशक पहले केवल 400 से बढ़कर आज 1.3 लाख हो गए हैं, और इनमें से लगभग 50 प्रतिशत टियर 2 और टियर 3 शहरों में आ रहे हैं।

यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका विशेष मान्यता की पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देवेंद्र फडणवीस तथा धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेताओं के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा और रोजगार भारत की विकास गाथा के मूल में बने रहें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य स्तर पर शैक्षिक सुधारों को आगे बढ़ाने, कौशल विकास और उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में उच्च शिक्षा को मजबूत

की भूमिका विशेष मान्यता की पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देवेंद्र फडणवीस तथा धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेताओं के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा और रोजगार भारत की विकास गाथा के मूल में बने रहें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य स्तर पर शैक्षिक सुधारों को आगे बढ़ाने, कौशल विकास और उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में उच्च शिक्षा को मजबूत

की भूमिका विशेष मान्यता की पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देवेंद्र फडणवीस तथा धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेताओं के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा और रोजगार भारत की विकास गाथा के मूल में बने रहें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य स्तर पर शैक्षिक सुधारों को आगे बढ़ाने, कौशल विकास और उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में उच्च शिक्षा को मजबूत

साहित्य से सॉफ्टवेयर तक - विश्व हिंदी सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, और हिंदी सप्ताह मनाने की परंपराएँ अब रस्मअदायगी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जबकि आँकड़े बताते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों और हिंदी गीतों की वजह से विश्व के लगभग 80 देशों में हिंदी-समझने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका, कनाडा, मॉरीशस, फिजी और खाड़ी देशों में हिंदी-भाषी समाज बड़ी ताकत बन चुका है। फिर भी विज्ञान, तकनीक और न्यायपालिका में हिंदी का स्थान हाशिए पर है।

आखिर दोष किसका?

दोष केवल अंग्रेजी या तथ्याकथित औपनिवेशिक मानसिकता का नहीं है। दोष उन नेताओं, नौकरशाहों और शिक्षा-नीति निर्माताओं का है, जो जनता से हिंदी में वोट तो माँगते हैं, पर अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल भेजते हैं।

गांधीजी ने चेताया था - किसी राष्ट्र की आत्मा उसकी भाषा में बसती है। पर हमने आत्मा को गिरवी रखकर शरीर को बेच दिया है।

भविष्य : अभी भी उम्मीद बाकी - यदि चीन, जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश अपनी भाषा में तकनीकी शिक्षा और शासन चला सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं? हिंदी न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत दावेदार बन सकती है— बशर्ते हम इसे विज्ञान, तकनीक और प्रशासन की मुख्यधारा में लाएँ।

हिंदी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह केवल भावना की भाषा रहेगी या ज्ञान की भी भाषा बनेगी।

ट्रंप की निजी खुन्नस का नतीजा

कहा जा रहा है कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध कम्पनी जैफरीज ने यह दावा किया है कि भारत पर थोपा गया बेतहाशा टैरिफ राष्ट्रपति ट्रम्प की निजी खुन्नस का नतीजा है जो कि आगे चल कर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए घातक है। कम्पनी के अनुसार ट्रम्प का ये कदम उनके सहयोग के विपरित है एवं अमेरिका के राष्ट्रीय हितों में भी सही नहीं है। इसी तरह से अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ का कहना है कि अमेरिका आज भारत के खिलाफ एक बड़े दबाव की तरह व्यवहार कर रहा लेकिन ऐसा करके वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कह सकते हैं कि भारत को धमकाने से वह ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के लिए एक आर्थिक विकल्प बनने की दिशा में धकेल रहा है। रिचर्ड वोल्फ का कहना है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है एवं आज भारत को यह बताना कि उसे क्या करना चाहिए यह तो एक तरह से एक चुहे का अपने एक साथी को मुक्का मारने जैसा है एवं उनका यह भी कहना है कि अगर अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बन्द कर देता है तो भारत को अपने निर्यात बेचने के लिए अन्य जगह मिल जायेगी और इस कदम से केवल ब्रिक्स देशों को मजबूती मिलेगी, अतः कहा जा सकता है कि भारत पर 50% टैरिफ लागू करना अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यक्तिगत खुन्नस का ही नतीजा है।

- **मनमोहन राजावत**, राजापुर



छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष

बदला दौर, आई चेहरों पर खुशहाली की झलक



सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से हो रहा सकारात्मक सामाजिक- आर्थिक बदलाव

छत्तीसगढ़ राज्य इस वर्ष 2025 में अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ में अपनी सतत विकास यात्रा शुरू की। इस विकास यात्रा के दौरान कई चुनौतियां भी आईं। राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद अब तेजी के साथ सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है। राज्य में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और लोगों के चेहरे पर समृद्धि और खुशहाली की झलक भी नजर आने लगी है। सरकार ने सामाजिक आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण की ऐसी योजनाएं तैयार की हैं, जिनके प्रभाव से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश के विकसित राज्यों में से एक होगा। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने अनेक चुनौतियों के बावजूद सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य ने औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में संतुलित विकास करते हुए देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। आगामी वर्षों में छत्तीसगढ़ को हरित विकास, डिजिटल नवाचार और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता देते हुए और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने की जरूरत है। यदि यही गति और समर्पण बना रहा, तो छत्तीसगढ़ “समृद्ध छत्तीसगढ़” की अवधारणा को साकार करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान सुनिश्चित करेगा।

सतत् विकास की राह

शिक्षा

सन् 2025

- शिक्षा सूचकांक: 0.520
- 32 हजार 461 प्राइमरी स्कूल
- महिला साक्षरता 70% से अधिक
- 09 शासकीय और 17 निजी विवि
- 15 मेडिकल कॉलेज

सन् 2000

- शिक्षा सूचकांक: 0.249
- प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सीमित, ग्रामीण क्षेत्रों में कमी
- महिला साक्षरता 50% से कम
- उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या कम

स्वास्थ्य

सन् 2025

- स्वास्थ्य सूचकांक: 0.672
- शिशु मृत्यु दर: प्रति हजार जीवित जन्म पर 38

सन् 2000

- स्वास्थ्य सूचकांक: 0.585
- शिशु मृत्यु दर: प्रति हजार जीवित जन्म पर 77
- ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा कमजोर

उद्योग

सन् 2025

- औद्योगिक योगदान: 42.4%
- इस्पात, सीमेंट, बिजली उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में
- बड़े औद्योगिक निवेश क्षेत्र का विस्तार और औद्योगिक पार्क स्थापित

सन् 2000

- औद्योगिक योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 30%
- प्रमुख रूप से खनन और इस्पात आधारित उद्योग
- सीमित निवेश व बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की कमी

रोजगार

सन् 2025

- बेरोजगारी दर: 2.4%
- महिला श्रम भागीदारी दर: 59.8%
- महिला समूह योजनाओं से रोजगार में वृद्धि
- कृषि के साथ उद्योग, आईटी, पर्यटन, सेवा क्षेत्र व स्वरोजगार में भी रोजगार के अवसर

सन् 2000

- बेरोजगारी दर लगभग 6%
- महिला श्रम भागीदारी दर 30%
- स्वरोजगार योजनाएं सीमित
- छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर आबादी सिर्फ खेती और पारंपरिक कामों पर निर्भर थी

कृषि

सन् 2025

- 21.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विस्तार
- सिंचाई नेटवर्क और खरीदी केंद्रों समेत उत्पादन तकनीक को बढ़ावा
- धान उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में

सन् 2000

- 13.28 लाख हेक्टेयर थी सिंचाई क्षमता
- सिंचाई के सीमित संसाधन, वर्षा पर निर्भरता ज्यादा, तकनीक की कमी
- कृषि कार्य हेतु बैल और पारंपरिक औजारों पर निर्भरता



25 वर्षों की विकास यात्रा

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जब यह मध्यप्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। जनजातीय बहुल यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, सांस्कृतिक विविधता और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। अपने गठन के 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास की एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा तय की है। यह यात्रा राज्य की आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए प्रयासों का सजीव प्रमाण है।

आर्थिक क्षेत्र में प्रगति

छत्तीसगढ़ ने बीते दो दशकों में आर्थिक मोर्चे पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। खनिज संसाधनों से समृद्ध यह राज्य देश की इस्पात, कोयला और बिजली उत्पादन में अग्रणी है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विशेष रूप से मिलाई, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर जैसे शहरों में तेजी से प्रगति हुई है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीति ने निवेशकों को आकर्षित किया है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। राज्य के बजट का आकार कई गुना बढ़ा है जिससे अधोसंरचना और सामाजिक विकास में प्रगति आई है।

कृषि और ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ को “धान का कटोरा” कहा जाता है। कृषि इस राज्य की रीढ़ है और किसानों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। बकाया धान बोनस भुगतान, ₹3100 प्रति विंटेनल की दर से प्रति एकड़ 21 विंटेनल धान खरीदी, सौर सुजला योजना जैसी योजनाएं किसानों को समृद्धि की ओर ले जा रही हैं। इन योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। जल-संसाधनों के बेहतर उपयोग और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

राज्य सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विद्यालयों के अधोसंरचना में सुधार, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, पीएम श्री विद्यालय, छात्रवृत्ति योजनाएं और “शालाओं का युक्तियुक्तकरण” जैसे कदमों से शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में मजबूती आई है और शहरों से लेकर गांवों तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। नए मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से सुदूर इलाकों तक लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुनिश्चित हुई है।

सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास

छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल लगातार विस्तृत हो रहा है। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राज्य सरकार की योजनाएं प्रभावी साबित हुई हैं। रेलवे, हवाई सेवा और नगरीय ढांचे में सुधार ने कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है। रायपुर का नया रेल कॉरिडोर, रायपुर- विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे, रायपुर-धनबाद एक्सप्रेस वे नई सड़क परियोजना, जगदलपुर हवाई सेवा और बिलासपुर स्मार्ट सिटी परियोजना इसके उदाहरण हैं।

राज्य का बजट आकार

- 2001-02- 3,999 करोड़
- 2025-26- 1,65,000 करोड़

राज्य सकल घरेलू उत्पाद

- 2001-02- 25,845 करोड़
- 2025-26- 6,35,918 करोड़ (अनुमानित)

बेरोजगारी दर

- 2017-18- 3.5%
- 2025-26- 2.5%

शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या

- 2001-02- 21000
- 2024-25- 278605

विश्वविद्यालय

- 2000 में 4
- 2025 में 26

जिला अस्पताल

- 2001-02- 6
- 2025-26- 30

राष्ट्रीय राजमार्ग

- 2001-02- 1810 किलोमीटर
- 2022-23- 3620.450 किलोमीटर

स्टेट हाईवे

- 2001-02- 2074 किलोमीटर
- 2025-26- 4310 किलोमीटर

ग्रामीण सड़क

- 2001-02- 28393 किलोमीटर
- 2022-23- 160116 किलोमीटर

सामाजिक- आर्थिक बदलाव लाने वाली योजनाएं



महतारी वंदन योजना

माताओं- बहनों को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता

तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक वृद्धि

तेंदूपत्ता संग्राहकों का संग्रहण पारिश्रमिक ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मानक बोरा

नियद नेल्ला नार योजना

बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंपों के समीप स्थापित 327 गांवों में तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समन्वित योजना कार्यक्रम

बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण

आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए स्थापित विशेष प्राधिकरण



चरण पादुका योजना

तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण

सौर सुजला योजना

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप की सहायता

कृषक उन्नति योजना

किसानों पर फसल उत्पादन के लागत मूल्य का बोझ कम करने के लिए आदान सहायता

नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम

इस तीव्र अभियान के तहत पिछले 20 महीने के अंदर 450 से अधिक नक्सलियों को किया न्यूट्रलाइज, 1589 से अधिक ने किया आत्मसमर्पण